SHODHPATRA: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND HUMANITIES
E-ISSN: 3048-6041 | Volume- 3, Issue- 3 | March 2026

पश्चिम एशिया का सामरिक संकट और वैश्विक आर्थिक प्रभाव: भारत की कूटनीतिक चुनौतियाँ और अवसर

महेंद्र पाल
प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
ढाबां झलार श्री गंगानगर, राजस्थान

सारांश

पश्चिम एशिया में उभरता सामरिक संकट, विशेष रूप से ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक शक्ति-संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर व्यापक रूप से पड़ रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र इस संकट के ऐतिहासिक, वैचारिक तथा सामरिक कारणों का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह अध्ययन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों—जैसे तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मुद्रास्फीति—का मूल्यांकन करता है। विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यह शोध भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक हितों तथा पश्चिम एशिया में कार्यरत भारतीय प्रवासी समुदाय पर इस संकट के प्रभावों का अध्ययन करता है। भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" पर आधारित विदेश नीति इस संदर्भ में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। यह संकट एक बहुआयामी वैश्विक चुनौती है, जिसके समाधान के लिए प्रभावी कूटनीतिक प्रयास और बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक हैं। साथ ही, यह भारत के लिए न केवल चुनौतियाँ, बल्कि वैश्विक भूमिका को सुदृढ़ करने के अवसर भी प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: पश्चिम एशिया, ईरान–इज़रायल–संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध, सामरिक संकट, वैश्विक आर्थिक प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा, हॉर्मुज जलडमरूमध्य, भू-राजनीति, भारत की विदेश नीति, कूटनीतिक चुनौतियां, रणनीतिक स्वायत्तता, वैश्विक शक्ति संतुलन

प्रस्तावना

पश्चिम एशिया समकालीन वैश्विक राजनीति का एक अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र रहा है, जहाँ भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता तथा वैचारिक मतभेदों ने निरंतर अस्थिरता को जन्म दिया है। विशेष रूप से ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बढ़ता तनाव इस क्षेत्रीय संकट को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित कर रहा है। यह संघर्ष केवल सैन्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों की संरचना पर भी व्यापक रूप से पड़ रहा है।

विगत दशकों में पश्चिम एशिया में शक्ति-संतुलन की राजनीति ने नए आयाम ग्रहण किए हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इज़रायल की सुरक्षा चिंताएँ तथा अमेरिका की क्षेत्रीय नीतियाँ इस त्रिकोणीय संबंध को जटिल बनाती हैं।

Published: 27 March 2026
DOI: https://doi.org/10.70558/SPIJSH.2026.v3.i3.45621
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

इसके अतिरिक्त, प्रॉक्सी युद्ध, साइबर हमले तथा सामरिक गठबंधनों का पुनर्गठन इस संकट को और अधिक गहरा करते हैं। विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर बढ़ता तनाव गंभीर चुनौती है, क्योंकि विश्व की एक बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति इसी मार्ग से संचालित होती है। इस संकट के वैश्विक आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। विकासशील देशों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक गहरा होता है, जहाँ ऊर्जा आयात पर निर्भरता अधिक होती है। इस संदर्भ में रूस और चीन जैसी शक्तियों की भूमिका भी वैश्विक शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर रही है।

भारतीय संदर्भ में, पश्चिम एशिया का यह संकट विशेष महत्व रखता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है, साथ ही यहाँ कार्यरत भारतीय प्रवासी समुदाय भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसी स्थिति में भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" पर आधारित विदेश नीति, जो विभिन्न वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है, अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य पश्चिम एशिया में उभरते सामरिक संकट तथा उसके वैश्विक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करते हुए भारत की कूटनीतिक चुनौतियों और संभावित अवसरों का समग्र अध्ययन करना है। यह अध्ययन वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को समझने के साथ-साथ भविष्य की नीति-निर्माण प्रक्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र गुणात्मक (Qualitative) एवं वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है, जिसमें पश्चिम एशिया के सामरिक संकट—विशेष रूप से ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संबंधों—का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें शोध-पत्र, पुस्तकों, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों तथा विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोत शामिल हैं। ऐतिहासिक एवं समकालीन विश्लेषण के माध्यम से संघर्ष की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया गया है, जबकि केस स्टडी दृष्टिकोण के अंतर्गत हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण सामरिक पहलुओं को शामिल किया गया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण द्वारा रूस और चीन की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है तथा यथार्थवाद और उदारवाद जैसे सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, नीति-विश्लेषण के माध्यम से भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता का अध्ययन किया गया है।

संघर्ष के कारण एवं पृष्ठभूमि

पश्चिम एशिया का वर्तमान सामरिक संकट केवल तात्कालिक घटनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं, वैचारिक टकरावों और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं का जटिल समागम है। विशेष रूप से ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य विकसित त्रिकोणीय संबंध इस संकट की केंद्रीय धुरी के रूप में उभरते हैं। 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन में आए परिवर्तन ने न केवल अमेरिका–ईरान संबंधों को शत्रुतापूर्ण बनाया, बल्कि इज़रायल–ईरान विरोध को भी वैचारिक और सामरिक दोनों स्तरों पर तीव्र कर दिया।

इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील आयाम ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसे इज़रायल और अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखते हैं। इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, कूटनीतिक दबावों और सैन्य विकल्पों की संभावनाओं ने इस मुद्दे को और अधिक जटिल बना दिया है। दूसरी ओर, ईरान स्वयं

को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु विभिन्न सहयोगी समूहों और प्रॉक्सी नेटवर्क के माध्यम से अपना प्रभाव विस्तार करता रहा है, जिससे पश्चिम एशिया में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति-संतुलन की राजनीति तीव्र हुई है। यह प्रतिस्पर्धा केवल वैचारिक या कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देशों में प्रॉक्सी युद्धों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती है। इस प्रकार, यह संघर्ष बहुस्तरीय स्वरूप ग्रहण कर चुका है, जिसमें सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक सभी आयाम परस्पर अंतर्संबंधित हैं। हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा इस संकट को वैश्विक आयाम प्रदान करती है। विश्व की एक बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति इसी मार्ग से संचालित होती है, अतः यहाँ उत्पन्न किसी भी प्रकार का तनाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

अतः स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया का यह सामरिक संकट किसी एक कारक का परिणाम न होकर ऐतिहासिक विरासत, वैचारिक विरोध, सामरिक महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक शक्ति-राजनीति के अंतःक्रियात्मक प्रभावों से निर्मित एक जटिल परिघटना है। यही जटिलता इसे न केवल क्षेत्रीय, बल्कि वैश्विक स्तर पर अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक मुद्दा बनाती है, जिसके समाधान हेतु संतुलित, बहुपक्षीय और दूरदर्शी कूटनीतिक दृष्टिकोण अनिवार्य है।

वर्तमान परिदृश्य एवं सामरिक आयाम

वर्तमान में पश्चिम एशिया का सामरिक परिदृश्य अत्यंत जटिल, अस्थिर और बहुआयामी स्वरूप ग्रहण कर चुका है, जहाँ ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य तनाव निरंतर गहराता जा रहा है। यह संघर्ष अब पारंपरिक युद्ध की सीमाओं से आगे बढ़कर हाइब्रिड युद्ध (Hybrid Warfare) के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के स्थान पर अप्रत्यक्ष रणनीतियाँ—जैसे प्रॉक्सी युद्ध, साइबर हमले, ड्रोन तकनीक और खुफिया अभियानों—का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान समर्थित ठिकानों पर लक्षित हमले तथा ईरान द्वारा क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से जवाबी कार्रवाइयों ने इस संघर्ष को अधिक खतरनाक बना दिया हैं।

इस परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण आयाम प्रॉक्सी युद्धों का विस्तार है। सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देशों में विभिन्न सशस्त्र समूहों और राजनीतिक गुटों के माध्यम से प्रभाव स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा ने क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इन संघर्षों में स्थानीय और वैश्विक शक्तियों की अप्रत्यक्ष भागीदारी ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है, जिससे यह क्षेत्र निरंतर संघर्ष और अस्थिरता का केंद्र बना हुआ है। तकनीकी दृष्टि से भी यह संघर्ष नई दिशा ले रहा है। ड्रोन हमलों, मिसाइल प्रणालियों और साइबर युद्ध के बढ़ते उपयोग ने युद्ध की प्रकृति को अधिक सटीक, तीव्र और अप्रत्याशित बना दिया है। इससे न केवल सैन्य जोखिम बढ़े हैं, बल्कि नागरिक संरचनाओं और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर भी खतरा उत्पन्न हुआ है।

सामरिक दृष्टि से हॉर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व इस पूरे संकट का केंद्रबिंदु है। यह जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, जहाँ से विश्व के कुल तेल परिवहन का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव या अवरोध अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी कारण, अमेरिका सहित कई वैश्विक शक्तियाँ इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखती हैं, ताकि ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्तमान परिदृश्य में सामरिक गठबंधनों का पुनर्गठन भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक ओर अमेरिका और इज़रायल के बीच मजबूत सहयोग है, वहीं दूसरी ओर ईरान का रूस और चीन के साथ बढ़ता सामरिक संबंध वैश्विक शक्ति-संतुलन को नए आयाम प्रदान कर रहा है। यह उभरता हुआ ध्रुवीकरण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा को और अधिक तीव्र बनाता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया का वर्तमान सामरिक परिदृश्य बहुस्तरीय, गतिशील और अत्यंत संवेदनशील है, जिसमें सैन्य, तकनीकी, आर्थिक और कूटनीतिक सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं। यही जटिलता इस संघर्ष को न केवल क्षेत्रीय, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है।

वैश्विक आर्थिक प्रभाव

पश्चिम एशिया में उभरता सामरिक संकट, विशेष रूप से ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बढ़ते तनाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरे और बहुआयामी प्रभाव डाल रहा है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा बाजार, व्यापारिक गतिविधियों, वित्तीय स्थिरता तथा वैश्विक विकास दर पर परिलक्षित होता है। चूँकि पश्चिम एशिया विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, अतः इस क्षेत्र में उत्पन्न अस्थिरता का सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। इस संकट का सबसे प्रमुख आर्थिक प्रभाव तेल कीमतों में अस्थिरता के रूप में देखा जाता है। किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि, प्रतिबंध या तनावपूर्ण स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव आता है। विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, वहाँ किसी भी प्रकार का व्यवधान विश्व बाजार में आपूर्ति संकट उत्पन्न कर सकता है। इससे ऊर्जा लागत में वृद्धि होती है, जो परिवहन, उत्पादन और उपभोग की लागत को बढ़ाकर व्यापक आर्थिक दबाव उत्पन्न करती है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पर पड़ता है। पश्चिम एशिया एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संपर्क क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अस्थिरता के कारण समुद्री मार्गों और व्यापारिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, वैश्विक बाजारों में वस्तुओं की कमी और कीमतों में वृद्धि देखने को मिलती है, जो अंततः मुद्रास्फीति (Inflation) को बढ़ावा देती है। इस संकट का प्रभाव वित्तीय बाजारों पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ने के कारण शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव आता है और सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की ओर झुकाव बढ़ता है, जैसे सोना और अमेरिकी डॉलर। इससे वैश्विक पूंजी प्रवाह प्रभावित होता है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न होती है। विकासशील और ऊर्जा-आयातक देशों पर इस संकट का प्रभाव और भी अधिक गहरा होता है। इन देशों को बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण अपने आयात बिल में वृद्धि का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके चालू खाते (Current Account) और राजकोषीय संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही, उच्च मुद्रास्फीति के कारण आम जनता की क्रय-शक्ति में कमी आती है, जो आर्थिक विकास को धीमा कर देती है।

अंततः, यह संकट वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अनिश्चितता और अस्थिरता को बढ़ावा देता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और विकास की संभावनाएँ प्रभावित होती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति मंद पड़ सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया का सामरिक संकट केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक वैश्विक आर्थिक चुनौती के रूप में उभर रहा है, जिसके समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और स्थिरता आवश्यक है।

वैश्विक शक्तियों की भूमिका

पश्चिम एशिया के वर्तमान सामरिक संकट को समझने के लिए वैश्विक शक्तियों की भूमिका का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है, यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संतुलन की व्यापक प्रतिस्पर्धा का प्रतिबिंब है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियाँ इस क्षेत्र में अपने-अपने रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के आधार पर सक्रिय रूप से संलग्न हैं। इन शक्तियों की नीतियाँ न केवल क्षेत्रीय घटनाक्रम को प्रभावित करती हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा भी निर्धारित करती हैं। सबसे प्रमुख भूमिका संयुक्त राज्य अमेरिका की रही है, जो लंबे समय से पश्चिम एशिया में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित है। अमेरिका का

मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में अपने सामरिक हितों की रक्षा करना, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखना तथा अपने प्रमुख सहयोगी इज़रायल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी कारण अमेरिका ने इस क्षेत्र में व्यापक सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है और विभिन्न राजनीतिक एवं कूटनीतिक माध्यमों से अपनी भूमिका को सुदृढ़ किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की कठोर नीति, आर्थिक प्रतिबंधों का प्रयोग, तथा क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करना इस रणनीति का हिस्सा हैं। रूस ने हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया है, विशेष रूप से सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से। रूस का उद्देश्य इस क्षेत्र में अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना, पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देना तथा ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका को स्थापित करना है। ईरान के साथ रूस के सामरिक संबंध भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जो क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को प्रभावित करते हैं।

चीन ने भी पश्चिम एशिया में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, यद्यपि उसका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत आर्थिक और कूटनीतिक रहा है। चीन की ऊर्जा आवश्यकताएँ इस क्षेत्र से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण वह स्थिरता और सहयोग को प्राथमिकता देता है। "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव" (BRI) के माध्यम से चीन इस क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे और व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। साथ ही, चीन ईरान सहित अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है, जिससे उसकी वैश्विक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। इन प्रमुख शक्तियों के अतिरिक्त, यूरोपीय देशों की भूमिका भी उल्लेखनीय है, जो इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने और कूटनीतिक समाधान को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। यूरोपीय संघ ने विशेष रूप से ईरान के परमाणु समझौते (JCPOA) को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यद्यपि इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी शांति स्थापना और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, लेकिन महाशक्तियों के परस्पर विरोधी हितों के कारण उनकी भूमिका अपेक्षाकृत सीमित रही है। समग्र रूप से देखा जाए तो पश्चिम एशिया का सामरिक संकट वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, सहयोग और संघर्ष का एक जटिल मिश्रण प्रस्तुत करता है। अमेरिका की सैन्य और राजनीतिक सक्रियता, रूस की रणनीतिक पुनर्स्थापना, तथा चीन की आर्थिक कूटनीति मिलकर एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर संकेत करती हैं। यह परिदृश्य न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को भी तेज करता है।

भारत पर प्रभाव, चुनौतियाँ एवं अवसर

पश्चिम एशिया में उभरता सामरिक संकट, ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, भारत के लिए बहुआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ, व्यापारिक हित, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा तथा उसकी विदेश नीति की दिशा इस क्षेत्रीय अस्थिरता से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। इसलिए यह संकट भारत के लिए केवल बाहरी मुद्दा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौती भी है। सर्वाधिक प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। ऐसे में क्षेत्र में अस्थिरता या हॉर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार का अवरोध भारत के ऊर्जा आयात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इससे तेल कीमतों में वृद्धि होती है, जो घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति, परिवहन लागत और आर्थिक विकास पर दबाव डालती है।

दूसरा महत्वपूर्ण आयाम प्रवासी भारतीयों और व्यापारिक हितों से जुड़ा है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय कार्यरत हैं, जो भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा (remittances) भेजते हैं। क्षेत्रीय तनाव या युद्ध की स्थिति में इन प्रवासियों की सुरक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। साथ ही, इस क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार भी बाधित हो सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस संकट का तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक संतुलन पर पड़ता है। भारत के ईरान,

इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका—तीनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष का समर्थन करना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि भारत "रणनीतिक स्वायत्तता" (Strategic Autonomy) की नीति अपनाते हुए संतुलित कूटनीति का पालन करता है, ताकि वह सभी पक्षों के साथ अपने संबंधों को बनाए रख सके।

हालाँकि, इन चुनौतियों के साथ-साथ भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवसर भी निहित हैं। सबसे पहले, यह संकट भारत को अपनी ऊर्जा नीति में विविधीकरण (Diversification) की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों (renewable energy) का विकास और नए आपूर्तिकर्ताओं की खोज। इससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है। दूसरा, भारत इस स्थिति का उपयोग कूटनीतिक अवसर के रूप में कर सकता है। एक संतुलित और तटस्थ शक्ति के रूप में भारत क्षेत्रीय संवाद और शांति प्रयासों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। इससे उसकी वैश्विक छवि एक जिम्मेदार और उभरती शक्ति के रूप में मजबूत हो सकती है। तीसरा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव भारत के लिए आर्थिक अवसर भी प्रस्तुत करता है। यदि भारत अपनी औद्योगिक क्षमता और व्यापारिक नेटवर्क को सुदृढ़ करता है, तो वह वैश्विक निवेश और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

अतः स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया का यह सामरिक संकट भारत के लिए चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण प्रस्तुत करता है। एक ओर जहाँ यह ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन और आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, वहीं दूसरी ओर यह भारत को अपनी नीतियों को सुदृढ़ करने, वैश्विक भूमिका को विस्तार देने और दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है।

विश्लेषण एवं चर्चा

पश्चिम एशिया का वर्तमान सामरिक संकट केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों, शक्ति-संतुलन की राजनीति तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य तनाव को समझने के लिए यथार्थवाद (Realism) और उदारवाद (Liberalism) जैसे प्रमुख सिद्धांतों के दृष्टिकोण से विश्लेषण आवश्यक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य अपने राष्ट्रीय हितों और शक्ति की अधिकतम प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। इस संदर्भ में देखा जाए तो ईरान, इज़रायल और अमेरिका के बीच संघर्ष मुख्यतः शक्ति-संतुलन और सुरक्षा की प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। इज़रायल अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए आक्रामक रणनीतियाँ अपनाता है, जबकि ईरान क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने और अपने प्रभाव को विस्तार देने का प्रयास करता है। दूसरी ओर, अमेरिका इस क्षेत्र में अपने सामरिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। इस प्रकार, यह संघर्ष यथार्थवाद के उस सिद्धांत को पुष्ट करता है, जिसमें शक्ति और सुरक्षा को सर्वोपरि माना जाता है।

इसके विपरीत, उदारवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संस्थागत व्यवस्था और कूटनीतिक संवाद को महत्व देता है। इस परिप्रेक्ष्य में, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय समझौते तथा बहुपक्षीय वार्ताएँ इस संकट के समाधान के संभावित माध्यम माने जाते हैं। हालांकि, व्यावहारिक स्तर पर इन संस्थाओं की प्रभावशीलता सीमित दिखाई देती है, क्योंकि महाशक्तियों के परस्पर विरोधी हित और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सहयोग की संभावनाओं को बाधित करते हैं। उदाहरणस्वरूप, ईरान के परमाणु मुद्दे पर हुए समझौते और उसके बाद उत्पन्न विवाद यह दर्शाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितनी आसानी से राजनीतिक परिस्थितियों के कारण प्रभावित हो सकता है। इस संकट का विश्लेषण "हाइब्रिड युद्ध" (Hybrid Warfare) की अवधारणा के संदर्भ में भी किया जा सकता है, जिसमें पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ साइबर हमले, आर्थिक प्रतिबंध, सूचना युद्ध और प्रॉक्सी युद्ध शामिल होते हैं। वर्तमान परिदृश्य में इन सभी

तत्वों का व्यापक उपयोग देखा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक संघर्ष अब बहुआयामी और जटिल स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यह संकट "रणनीतिक स्वायत्तता" (Strategic Autonomy) की नीति की प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है। भारत ने ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका—तीनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है। यह नीति यथार्थवाद और उदारवाद के बीच संतुलन स्थापित करती है, जहाँ एक ओर भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक संवाद को भी महत्व देता है। यह संकट वैश्विक शक्ति-संतुलन में हो रहे परिवर्तन को भी उजागर करता है, जहाँ रूस और चीन जैसी शक्तियाँ पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे रही हैं। यह उभरता हुआ बहुध्रुवीय (Multipolar) विश्व व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और जटिल बना रही है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पश्चिम एशिया का यह संकट केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-राजनीति, वैचारिक मतभेदों और आधुनिक युद्ध तकनीकों का समेकित परिणाम है। इसके समाधान के लिए आवश्यक है कि शक्ति-आधारित दृष्टिकोण के साथ-साथ सहयोग, संवाद और बहुपक्षीय कूटनीति को भी समान महत्व दिया जाए।

नीतिगत सुझाव

पश्चिम एशिया में उभरते सामरिक संकट के संदर्भ में भारत के लिए एक संतुलित, व्यावहारिक और दूरदर्शी नीति अपनाना अत्यंत आवश्यक है। ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक स्थिरता में भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

- सबसे पहले, भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए तेल और गैस आयात के स्रोतों का विविधीकरण आवश्यक है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के विकास को प्रोत्साहित कर दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सकती है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील मार्गों पर निर्भरता कम करना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- भारत को अपनी कूटनीतिक संतुलन नीति (Balanced Diplomacy) को ओर अधिक सुदृढ़ करना चाहिए। भारत के ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका—तीनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं, अतः किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय संतुलित और स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। "रणनीतिक स्वायत्तता" (Strategic Autonomy) की नीति को बनाए रखते हुए भारत को बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- भारत को पश्चिम एशिया में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। संकट की स्थिति में त्वरित निकासी (Evacuation) और सुरक्षा उपायों के लिए एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, भारतीय श्रमिकों और पेशेवरों के हितों की रक्षा हेतु द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत किया जाना चाहिए।
- भारत को इस स्थिति का उपयोग आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए करना चाहिए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में हो रहे बदलाव के बीच भारत अपने विनिर्माण (Manufacturing) और निर्यात क्षमता को बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित कर सकता है। इससे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है।

- भारत को रक्षा और सामरिक सहयोग को सुदृढ़ करना चाहिए, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) के क्षेत्र में। हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए आवश्यक है। इसके लिए क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।
- भारत को कूटनीतिक मध्यस्थता और शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। एक जिम्मेदार और उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत संवाद और सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे सकता है। इससे उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि और प्रभाव दोनों में वृद्धि होगी।

अंततः, भारत को अपनी विदेश नीति में लचीलापन और यथार्थवाद बनाए रखना चाहिए, ताकि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार त्वरित और प्रभावी निर्णय लिए जा सकें। इस प्रकार, संतुलित कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुदृढ़ता और सामरिक जागरूकता के माध्यम से भारत न केवल इस संकट की चुनौतियों का सामना कर सकता है, बल्कि उभरते अवसरों का भी लाभ उठा सकता है।

निष्कर्ष

पश्चिम एशिया का वर्तमान सामरिक संकट समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं और बहुआयामी स्वरूप का सशक्त उदाहरण है। ईरान, इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बढ़ते तनाव ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डाला है। यह स्पष्ट है कि यह संघर्ष केवल सीमित भौगोलिक दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव विश्वव्यापी हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस संकट के मूल में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैचारिक मतभेद, क्षेत्रीय प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा तथा वैश्विक शक्तियों की रणनीतिक नीतियाँ निहित हैं। वर्तमान परिदृश्य में यह संघर्ष पारंपरिक युद्ध की सीमाओं से आगे प्रॉक्सी युद्ध, साइबर हमलों और कूटनीतिक दबावों के माध्यम से संचालित हो रहा है। विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे सामरिक मार्गों पर बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।

वैश्विक आर्थिक स्तर पर, इस संकट ने तेल कीमतों में अस्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान तथा मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों को जन्म दिया है, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों पर अधिक दबाव पड़ा है। साथ ही, रूस और चीन जैसी शक्तियों की सक्रियता ने वैश्विक शक्ति-संतुलन को बहुध्रुवीय दिशा में परिवर्तित कर दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन गई है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यह संकट चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करता है। एक ओर ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा तथा कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है, वहीं दूसरी ओर यह स्थिति भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने, वैश्विक मंच पर सक्रिय भूमिका निभाने तथा आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने का अवसर भी प्रदान करती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया का यह सामरिक संकट एक जटिल और बहुआयामी वैश्विक चुनौती है, जिसके समाधान के लिए केवल शक्ति-आधारित दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। इसके लिए बहुपक्षीय सहयोग, प्रभावी कूटनीति और संवाद आधारित समाधान आवश्यक हैं। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह संतुलित, यथार्थवादी और दूरदर्शी नीति अपनाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे तथा वैश्विक शांति और स्थिरता में रचनात्मक योगदान दे।

संदर्भ सूची -

1. BBC News Hindi (2025). ईरान-इज़रायल तनाव और पश्चिम एशिया की स्थिति

2. Waltz, Kenneth N. (1979). Theory of International Politics.
3. Mearsheimer, John J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton & Company.
4. International Monetary Fund (2023). World Economic Outlook.
5. World Bank (2025). Global Economic Prospects.
6. International Energy Agency (2023). Oil Market Report.
7. पुष्पेश पंत (2019). अंतरराष्ट्रीय संबंध. मैकग्रा हिल एजुकेशन, नई दिल्ली।
8. वी. एन. खन्ना (2020). अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं वैश्विक राजनीति. विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
9. डॉ. एस. सी. सिंघल (2018). वैश्विक राजनीति और भारत. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
10. Ministry of External Affairs, India (2023). वार्षिक रिपोर्ट 2022–23।
11. Observer Research Foundation (2023). भारत और पश्चिम एशिया: सामरिक परिप्रेक्ष्य।